भारत सरकार

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 4027

मंगलवार, 25 मार्च, 2025 को उत्तर दिए जाने के लिए

इन्वेस्ट इंडिया के माध्यम से प्रत्यक्ष विदेशी निवेश

4027. श्री संजय हरिभाऊ जाधवः

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विगत पांच वर्षों और वर्ष 2024 (अप्रैल-दिसम्बर) के दौरान इन्वेस्ट इंडिया द्वारा प्रदत्त प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) संबंधी आंकड़ों का कंपनीवार ब्यौरा क्या है;

(ख) निवेश करने वाली कंपनी के नाम, मूल देश, निवेश के क्षेत्र/उद्योग, लाभार्थी राज्य और निवेश राशि का ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त अवधि के दौरान इन्वेस्ट इंडिया द्वारा कुल कितनी परियोजनाओं और निवेश मूल्य को सुगम बनाया गया तथा इन निवेशों का क्षेत्रवार ब्यौरा क्या है;

(घ) इन्वेस्ट इंडिया के माध्यम से और अधिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश आकर्षित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ङ) मुख्य कार्यकारी अधिकारी या प्रबंध निदेशक इन्वेस्ट इंडिया की जनप्रतिनिधियों से भेंट की समय-सारणी क्या है तथा इस प्रयोजनार्थ क्या प्रोटोकॉल निर्धारित किया गया है?

उत्तर

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री जितिन प्रसाद)

(क) से (ग): राष्ट्रीय निवेश संवर्धन और सुविधाप्रदाता एजेंसी होने के नाते इन्वेस्ट इंडिया भारत के व्यापक आर्थिक विजन की दिशा में सहायता प्रदान करता है, जिससे संभावित अंतर्राष्ट्रीय निवेशकों और देश के विविधतापूर्ण आर्थिक परिदृश्य के बीच का अंतर दूर होता है। इन्वेस्ट इंडिया की स्थापना का उद्देश्य भारत में निवेश करने के इच्छुक निवेशक के लिए प्रथम संपर्क बिंदु के रूप में कार्य करना है। यह प्रचारात्मक कार्य भी करता है तथा विशेष रूप से महानगरों के अलावा अन्य शहरों में वैश्विक निवेशक जागरूकता फैलाकर निवेश आकर्षित करता है। यद्यपि इन्वेस्ट इंडिया सुविधाप्रदाता की भूमिका निभाता है, तथापि

निवेश मूल रूप से व्यापक आर्थिक स्थितियों, नीतिगत फ्रेमवर्क और भारतीय बाजार की अंतर्निहित क्षमता को दर्शाता है। पिछले पांच वर्षों के दौरान इन्वेस्ट इंडिया की सहायता से प्राप्त प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) के आंकड़ों का विवरण डीपीआईआईटी द्वारा नहीं रखा जाता है। हालांकि, इन्वेस्ट इंडिया द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, अप्रैल 2023 से मार्च 2025 (दिनांक 22.03.2025) तक, इन्वेस्ट इंडिया ने कुल 4.1 बिलियन अमेरिकी डॉलर के सांकेतिक निवेश वाली परियोजनाओं में सहायता प्रदान की है, जिसमें 40 एफडीआई परियोजनाओं को शुरू करके 3.03 बिलियन अमेरिकी डॉलर का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश शामिल है। विवरण अनुबंध-I में दिया गया है।

(घ): भारत सरकार इन्वेस्ट इंडिया और अन्य संगठनों के जरिए उचित नीतिगत कार्यक्रमों के माध्यम से देश में अधिक एफडीआई आकर्षित करने के लिए एक समर्थकारी ईकोसिस्टम उपलब्ध कराती है। सरकार ने एक निवेशक-अनुकूल नीति तैयार की है, जिसमें रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण कुछ क्षेत्रों को छोड़कर अधिकांश क्षेत्र स्वत: अनुमोदन मार्ग के तहत 100% एफडीआई के लिए खुले हैं। 90% से अधिक एफडीआई अंतर्वाह स्वत: अनुमोदन मार्ग के तहत प्राप्त होता है। भारत, एफडीआई सीमा बढ़ाकर, विनियामक बाधाओं को दूर करके और ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस, अवसंरचना विकास और व्यावसायिक वातावरण में सुधार करने की दिशा में अन्य कदम उठाकर वैश्विक निवेशकों को आकर्षित करने के लिए निरंतर प्रगतिशील कदम उठा रहा है। उपर्युक्त के अलावा, सरकार एफडीआई नीति की नियमित आधार पर समीक्षा करती है ताकि इसे और अधिक निवेशक-अनुकूल बनाया जा सके और देश में निवेश अंतर्वाह में रुकावट पैदा करने वाली नीतिगत बाधाओं को दूर किया जा सके।

इसके अलावा, इन्वेस्ट इंडिया नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम (एनएसडब्ल्यूएस) का संचालन करता है, जो निवेशकों के लिए केंद्र और राज्य सरकारों से मंज़ूरी प्राप्त करने हेतु वन-स्टॉप डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म है। यह विनियामक बाधाओं को कम करता है और व्यवसायों के लिए पारदर्शिता बढ़ाता है।

(ङ): जब भी जन प्रतिनिधि कार्यालय से इन्वेस्ट इंडिया के सीईओ/प्रबंध निदेशक के साथ बैठक का अनुरोध प्राप्त होता है, तो अनुरोधकर्ता और इन्वेस्ट इंडिया के सीईओ एवं एमडी की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए प्राथमिकता दी जाती है।

*****

अनुबंध-I

दिनांक 25.03.2025 को उत्तर दिए जाने के लिए नियत लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 4027 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

इन्वेस्ट इंडिया की सहायता से प्राप्त एफडीआई के मामले (अप्रैल 2023 से मार्च 2025 (दिनांक 22.03.2025) तक क्षेत्रवार वितरण

क्षेत्र	कंपनियों की संख्या	निवेश मिलियन अमेरिकी डॉलर में
पूंजीगत वस्तुएं	4	49.4
निर्माण, लॉजिस्टिक्स, रेलवे	2	250
उपभोक्ता वस्तुएं	1	180
ईएसडीएम	4	139.6
आईटी-बीपीएम	4	43
चिकित्सा उपकरण	2	12.9
कागज और पैकेजिंग	2	164
वस्त्र	5	535.5
ऊर्जा	2	760
एफआईआई	1	232
ऑटोमोटिव	5	252.35
रसायन और उर्वरक	2	275
खेल-कूद	1	0.24
पशुपालन और डेयरी	1	84
फार्माबायोटेक-	2	54.3
पोत परिवहन और अंतर्देशीय जलमार्ग	1	1
दूरसंचार	1	0.8
कुल योग	**40**	**3034**

*****

भौगोलिक वितरण:

मूल देश	शुरू की गई परियोजनाओं की संख्या
यूएसए	10
ऑस्ट्रेलिया	1
साइप्रस	1
श्रीलंका	1
मॉरिशस	1
चीन	1
हांगकांग	1
इटली	1
जापान	3
लिचेन्स्टाइन	1
लक्समबर्ग	1
मलेशिया	1
कतर	1
सिंगापुर	3
साउथ कोरिया	3
स्विट्जरलैंड	2
रूस	1
फ्रांस	1
जर्मनी	1
न्यूजीलैंड	1
स्पेन	2
युनाइटेड किंगडम	2
कुल योग	**40**

प्राप्तकर्ता राज्य	शुरू की गई परियोजनाओं की संख्या
गोवा	1
आंध्र प्रदेश	1
असम	1
छत्तीसगढ़	1
गुजरात	6
हरियाणा	3
कर्नाटक	5
महाराष्ट्र	6
ओडिशा	3
पंजाब	1

राजस्थान	1
तमिलनाडु	4
दिल्ली	1
जम्मू और कश्मीर	1
मध्य प्रदेश	2
एकाधिक राज्य	1
तेलंगाना	1
पश्चिम बंगाल	1
कुल योग	**40**

*****